JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सरकारी योजनाएं : कृषि में नवाचार और ग्रामीण समृद्धि की कुंजी (जनपद बदायूं के जगत विकासखंड के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन)

डा. नीतू गुप्ता

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)

ने. मे. शि. ना. दास पीजी कॉलेज बदायूँ, उ० प्र०

सारांश

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व प्राचीन काल से ही रहा हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ–साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 प्रतिशत जनसंख्या वाला देश भारत है देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है भारत देश की जनसंख्या का लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती हैं वर्तमान समय में देश की जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषि और इससे जुड़े गतिविधियों (2011 की जनगणना के अनुसार) में लगा है और देश के सकल मूल संवर्धन चालू कीमत पर 2019–20 में इसकी हिस्सेदारी 17.8% है जो बढ़कर 2020–21 में 19.9% हो गया । भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि एक महत्वपूर्ण आधार है, और उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के किसान आज भी 70% कृषि पर ही निर्भर हैं। कृषि मानसून पर निर्भर है, जिसे कभी–कभी कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों ही असफल रहे हैं" ग्रामीण विकास देश के विकास का प्रमुख हिस्सा है। महात्मा गांधी ने कहा था, "भारत गांव का देश है और इसकी आत्मा गांव में निवास करती है।" ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास असम्भव है। किसानो की आय और जीवन स्तर सुधार के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा कृषि तकनीकी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, जो कृषि से जुड़े होते हैं इसके अलावा, बाजार और वित्तीय सुविधाओं का विकास भी महत्वपूर्ण है ताकि कृषि सेक्टर को सुदृढ़ किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और तकनीकी उन्नति और कृषि ज्ञान भी अति आवश्यक है भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में कई कदम उठाए हैं जैसे की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और परंपरागत कृषि विकास योजना यह योजनाएं कृषि क्षेत्र के सुधार के साथ जोखिम को कम करने में मदद कर रही हैं इन योजनाओं से किसानों को सामूहिक रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है और उनकी आर्थिक सुरक्षा में सहायता प्रदान की जा रही है इस शोध पत्र के माध्यम से कृषि नवाचार जैसी योजनाओं से ग्रामीण विकास के संबंध में प्रकाश डाला गया है।

शब्द कुंजी–कृषि एवं ग्रामीण संबंधी सरकारी योजनाओं, कृषि नवाचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, कृषि एवं अर्थव्यवस्था

प्रस्थापना :

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विशेष महत्व प्राचीन काल से ही रहा है और वर्तमान समय में भी इस तत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कृषि देश के लोगों का जीविकोपार्जन साधन ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी है देश के उद्योग धंधे, विदेशी व्यापार विभिन्न योजनाओं की सफलता और राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि के उत्पादन पर ही निर्भर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों ही असफल रहे हैं।" ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ग्रामीणों के लिए मुख्य आय स्रोत होता है, जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसके अलावा कृषि उत्पादन उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति में मदद करता है, जो द्वितीय क्षेत्र उद्योग के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुटीर और लघु उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े और आर्थिक संगठन को समर्थन मिले प्रधानमंत्री ग्रामीण उद्योग योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण उद्योग योजना जैसी योजनाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करती है और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। देश में आजादी मिलने के बाद भी कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यह समस्याएं जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, प्राकृतिक आपदा आदि समाज में विकास की राह में बड़ी चुनौतियां हैं इन चुनौतियों का समाधान केंद्र सरकार, स्थानीय शासन और समाज की संगठनों के साथ जनता के सहयोग और सहभागिता के माध्यम से हो सकता है भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं को लागू करके कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया है जैसे किसान सम्मन निधि योजना कृषि सिंचाई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मनरेगा योजना ग्रीन फील्ड डेयरी योजना सोलर पंप योजना आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त समस्या दूर हुई है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कृषि सेक्टर में सुधार के लिए वास्तविक और प्रभावी हो सकता है इससे किसानों को सहायता प्रदान की जा सकती है जैसे की फसल नियोजन स्वास्थ्य निगरानी, बीमा सुविधा, बाजार की जानकारी और कृषि तकनीक उद्योगों और स्टार्टअप के विकास के लिए सहायता मिल सकती है साथ ही राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जलवायु परिवर्तन और कृषि में राष्ट्रीय नवाचार जैसी योजनाओं के लागू होने से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है और उन्हें मानसून और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाने में मदद मिल सकती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं का पारदर्शी बनाने हेतु पारदर्शी किसान सेवा योजना आरंभ की गई है इसका उद्देश्य है कृषि विभाग के द्वारा संचारित सभी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं को सूक्ष्म से व्यापक स्तर तक पहुंचाना है और इसे तुरंत और दोष रहित तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए जिसके फलस्वरूप अनाजों में विशेष रूप से चावलों का उत्पादन (मिलियन टन) 1950–51 में 20.58 और 2022–2023 में बढ़कर 135.54 हो गया तथा गेहूं का उत्पादन (मिलियन टन) 1950–51 में 6.46 और 2022 2023 में बढकर 112.74 हो गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड–19 महामारी के समय में खाद्यान्नो क्षेत्र में संतोक जनक प्रगति देखी गई है वर्ष 2020–21 के समय खाद्यान्नों के अंतर्गत 1297.95

लाख हेक्टर क्षेत्र में बुवाई की गई थी जबकि 2019–20 के दौरान 1269.94 लाख हेक्टेयर में बुवाई थी। इस प्रकार वुवाई के क्षेत्र में 28.00 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है । वर्ष 2020– 2021 के दौरान खाद्यान्नो का उत्पादन पिछले बर्ष के 297 5.05 प्राप्त की तुलना में 3107.42 लाख टन हुआ जो उत्पादन में 132.37 लाख टन की वृद्धि को दर्शाता है।

आज ग्रामीणों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना समावेशी और किसान केंद्रित समाधान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी हो सकता है इससे

कृषि सेक्टर में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर किसानों को सहायता प्रदान की जा सकते हैं जैसे की फसल नियोजन स्वास्थ्य की निगरानी और बीमा की सुविधा बाजार की जानकारी और किसी तकनीक उद्योगों और स्टार्टअप के विकास के लिए सहयोग के क्षेत्र में सहायता मिलेगी। मानसून पर निर्भर कृषि क्षेत्र में खाद उत्पादन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन और कृषि में राष्ट्रीय नवाचार जैसी योजनाओं के लागू होने से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है जो उन्हे मानसून और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाने में मदद कर सकते है। उ. प्र. सरकार के द्वारा समस्या का समाधान सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं को पारदर्शी बनाने हेतु पारदर्शी किसान सेवा योजना आरम्भ की गई इसका उद्देश्य है कृषि विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं को सूक्ष्म से व्यापक स्तर तक पहुंचाना है, और इसे तुरंत और दोष रहित तरीके से संपन्न किया जाना चाहिए । जिसके फलस्वरूप अनाजों में, विशेष रूप से चावल का उत्पादन) (मिलियन टन) 1950–51 में 20.58 और 2022–2023 में बढकर 135.54 हो गया तथा गेंहू का उत्पादन (मिलियन टन) 1950–51 मे 6.46 और 2022– 2023 में बढ़कर 112.74 हो गया है। जैसा कि हम सभी जानते है कि कोविड 19 महामारी के समय में खाद्यान्नों के क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति देखी गई है वर्ष 2020–2021 के समय खाद्यान्न के अन्तर्गत 1,297. 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई थी जबकि 2019–2020 के दौरान 1269.94 लाख हेक्टेयर में बुआई थी । इस प्रकार बुवाई के क्षेत्र में 28.00 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। बर्ष 2020– 2021 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष के 2,975–05 लाख टन की तुलना में 3,107.42 लाख टन हुआ जो उत्पादन में 132.37 लाख टन की वृदि दर्शाता है।''

पूर्व साहित्य का अध्ययन :

डा. चतुर्भुज मेमोरियल एवं डॉ. एस. सी. जैन (1991)

स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि "कृषि की सवार्धिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है यदि कृषि असफल रहती है तो सरकार एवं राष्ट्र दोनों ही असफल रहें है।" कृषि हमारे देश में केवल जीविकोपार्जन का साधन या उद्योग धन्धा ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डी है। देश के उद्योग–धन्धे, विदेशी व्यापार, विदेशी मुद्रा अर्जन, बिभिन्न योजनाओं की सफलता एवं राजनीतिक स्थायित्व भी कृषि पर निर्भर है।

महात्मा गांधी ने कहा, "भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव मे निवास करती है।" ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास असम्भव है।

शोधार्थी ज्योति निषाद डा. श्रीमती संतोष जैन ने अध्ययन कर स्पष्ट किया कि सरकार के द्वारा मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, जिससे किसानों एवं ग्रामीणों की आय में रोजगार में शिक्षा के स्तर में मूलभूत सुविधाओं के स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे है। साथ ही साथ स्वयं के विकास के साथ देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

कृषि अर्थशास्त्र दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, महर्षि दयानंद विश्व विधालय, रोहतक

कोल एवं हूबर ने कहा है कि " सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए कृषि विकास पहले होना चाहिए है" यह स्पष्ट होता है कि कृषि विकास से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि यह रोजगार, आय और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करता है, इसके बावजूद, कृषि विकास से आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलती है।

अजीत कुमार यादव (2018) के शोध लेख के अनुसार यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में पिछड़ गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए शिक्षा और कौशल विकास, जन स्वास्थ्य उत्पादकता मूल संसाधनों का विकास, निर्धनता, आधारभूत संरचना जैसे तत्वों की नवीन तकनीकी के माध्यम से सर्व सुलभ बनाने एवं गांवों में उद्यमिता को नया वातावरण देना होगा और यह सब तो तभी संभव है जब हम सामाजिक न्याय की अवधारणा को विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर अवसरों की समानता को जमीनी स्तर पर उतर सकेंगे।

डॉ. कौशल जैन कोठारी (2023) के शोध लेख के आधार पर शिक्षा एवं सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के मध्य सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं वह सरकारी योजनाओं से अधिक लाभ ले पाते है लेकिन जो व्यकि अशिक्षित होते हैं वह सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहते है क्योंकि वह सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक नहीं होतें है। इसलिए शिक्षा ही व्यक्ति का सर्वागीण विकास करती है वह व्यक्ति को जागरूक बनाती है।

भारत 2023 :

भारत सरकार ने वर्ष 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी दी थी। नीति का उद्देश्य खेती को अर्थिक जीवन शक्ति में सुधार तथा किसानों की शुद्ध आय में बढ़ोत्तरी करना । इस नीति के कई प्रावधानों को विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के जरिए लागू किया जा रहा है, जिनका कार्यान्वयन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालय द्वारा किया जा रहा हैं और सरकार के द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जो कि इस प्रकार है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना–यह योजना 1998 में प्रारम्भ की गई, इस योजना का उद्देश्य किसानों को अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण की प्राप्ति कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराना है। किसानों को 1 लाख 60 हजार रूपए का लोन इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है।

किसान टैक्टर योजना—इस योजना में किसानों को टैक्टर खरीदने पर 20 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। भारत सरकार ने किसानों का विकास और कल्याण करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना को शुरू किया है।

कुसुम योजना—इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा किसानों की सहायता के लिए लागू किया गया है जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे जिससे उन्हें पेट्रोल और डीजल के पंपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा 24 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी जिससे किसी भी समय किसान सिंचाई कर सकते हैं उन क्षेत्रों में अधिक लाभ मिलेंगे जहाँ सूखे के कारण फसल खराब हो जाती है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना—यह योजना 2019 को लागू की गई है। जो कि किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रुप में प्रति वर्ष रूपये 6000 रूपये की आर्थिक सहायता भारत सरकार के द्वारा दिए जाते है। यह आथिर्क सहायता 2000 रूपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना—यह योजना 2016 में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलो की सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। इस योजना में किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिए दो प्रतिशत प्रीमियम रबी की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

पीएम कृषि सिंचाई योजना—1 जुलाई 2015 में 'हर खेत को पानी के' आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग के क्षेत्र में सुधार का कार्य किया जा रहा है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना—मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रकार से एक रिपोर्ट कार्ड होता है। जिसमें मिट्टी के गुण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है । किसान को उसकी जमीन की गुणवता के आधार पर यह कार्ड दिया जाता है जो की 3 साल में 1 बार दिया जाता है। इस कार्ड का मुख्य उद्देश्य जैविक खादों और जैव उर्वरकों के साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक प्रबंधन बढ़ावा देना है।

जैविक खेती योजना—किसानों द्वारा अपनी फसलों से बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे उनके खेतों की उपजाऊ क्षमता लगातार कम होती जा रही है । हालाँकि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित की जा रही है, यहाँ तक की जैविक कृषि करनें वाले किसानों को योजनाओं के माध्यम से अनुदान देने के साथ ही उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना—"स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन" के नारे के साथ केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में एक सामाजिक कल्याण योजना "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना" की शुरूआत की है यह योजना एक धुँआरहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और वर्ष 2019 तक 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी।

आवास योजना—भारत सरकार की 2015 में शुरू की गई योजना के अन्तर्गत जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ है, उन्हें सरकार पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 01 फरवरी 2024 के बजट में कहा अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा।

आयुष्मान भारत योजना—इस योजना का उद्देश्य गरीब और समाज के निचले वर्ग तक आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाओ को पहुंचाना हैं इस कार्ड के माध्यम से केन्द्र सरकार के द्वारा सुनिश्चित अस्पतालों में 5 लाख रूपये तक का इलाज करवा सकते हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण—नागरिकों की सहभागिता से अधिक से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है।

मनरेगा योजना—यह ग्रामीण परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रमिक आजीविका का साधन है यह उन लोगों के लिए आय का स्रोत प्रदान करती है जो विशेष रूप से सूखा और फसल की विफलता के समय में रोजगार की तलाश में होते है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली—भारत सरकार के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्य और गैर खाद्य पदार्थों वितरित करने के लिए भारत के गरीबों को सब्सिडी दरों पर वितरित की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में देश भर के कई राज्यों में स्थापित उचित मूल्य की दुकानों (जिन्हें राशन की दुकानों के रूप में भी जाना जाता है) के नेटवर्क के माध्यम से मुख्य खाद्यान्न, जैसे गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे आवश्यक ईंधन शामिल हैं।

उन्नत बीज खाद्य वितरण योजना—इस योजना में किसानों को बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं।

अध्ययन का क्षेत्र—

भारत का उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से इस जनपद बदायूं का भाग 1.75 अधिक है। जनपद बदायूं गंगा और रामगंगा दो नदी के आव में स्थित है जनपद में 5 तहसील 15 ब्लॉक हैं जनपद विकासखंड की दूरी 16 कि. मी है जगत विकासखंड के अंतर्गत 72 ग्राम पंचायत विकास है । जगत ब्लॉक में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या 11913 है। जनपद में जनगणना उसके बाद आबाद ग्रामों का विकासखंड विवरण (2021—22) जनगणना 2011 के ग्रामों अनुसार की संख्या विकासखंड जगत में आबाद 102 गैर आबाद 10 कुल 112 संख्या है । जगत विकासखंड में जनसंख्या का घनत्व प्रतिशत कि.मी. 2010—2011 में 724.74, अनु. जन./जन.जा. का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2010—11 में 21.36 कुल मुख्य कर्मकारों का कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2010—2011 में 23.30 कृषि में लगे कर्मकारों का कुल मुख्य कर्मकारों प्रतिशत 2010—2011 में 84.03 पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकारों का कुल मुख्य प्रतिशत 2010—2011 में 1.65, कुल साक्षत्ता का प्रतिशत 2010—2011 में 54.00 है। जनपद जनसंख्या विकासखंड जगत में प्रति सौ आबाद ग्रामों पर बायोगैस संयंत्रों की संख्या 2010—2011 में 435.00 2020—2021 442.16, 2021—2022 में 442.16 हैं। गैस एवं जैविक खाद के रूप में उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिससे रासायनिक खाद का उपयोग कम हो सके और स्वास्थ्यवर्धक एवं उच्च गुणवत्ता वाले खाधान्नों का उत्पादन किया जा

सके। जनपद बदायूं के क्षेत्रों में चावल, गेंहू, जौ, बाजरा और सफेद चने की उपज होती है । बदायूँ मैन्था फसल के लिए मशहूर है देश का लगभग 40 प्रतिशत फीसदी मैन्था यहीं होता हैं ।

अध्ययन का उद्देश्य

1. किसानों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओ का जगत ब्लॉक में दी जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना।

2. कृषि के द्वारा प्राप्त आय से जगत ब्लॉक में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

परिकल्पना—

1. किसानों की आय में वृद्धि से गांव के विकास में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

2. सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओ का सीधा लाभ किसानो एवं गांव को मिल रहा है।

शोध पद्धति—प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़ों के संकलन के लिए बदायूँ जनपद के जगत ब्लॉक प्रयोग किया गया जिसमें निर्देशन पद्धति के अंतर्गत का लॉटरी प्रणाली के माध्यम से 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। चयनित उत्तरदाताओं से प्रश्नावली, अनुसूची एवं अवलोकन विधि द्वारा आंकड़ों को एकत्रित किया गया है प्रस्तुत अध्ययन में आवश्यकता अनुसार द्वितीय आंकड़ों के संकरण के लिए संबंधित ग्रंथों का अध्ययन किया है।

तालिका क्रमांक – 01

विभिन्न ग्रामीण सम्बन्धित सरकारी योजनाओं की लाभ स्थिति

क्र.सं.	सरकारी योजनाओं के नाम	लाभ हुआ	लाभ नहीं हुआ	योग
1.	किसान सम्मान निधि क्रेडिट कार्ड योजना	80	20	100
2.	किसान टैक्टर योजना	20	80	100
3.	कुसुम योजना	20	80	100
4.	पीएम किसान सम्मान निधि योजना	85	15	100
5.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	45	55	100
6.	पीएम कृषि सिंचाई योजना	40	60	100
7.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	30	70	100
8.	जैविक खेती योजना	20	80	100
9.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	95	05	100

10.	आवास योजना	90	10	100
11.	आयुष्मान भारत योजना	70	30	100
12.	मनरेगा योजना	90	10	100
13	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	100	00	100
14.	उन्नत बीज खादद्य वितरण योजना	95	05	100

स्रोत– प्रश्नावली/अनुसूची द्वारा संकलित

उपरोक्त तालिका व आरेख क्रमांक–1 के द्वारा स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना, आवास योजना, मनेरगा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उन्नत बीज खाद्य वितरण योजना का 10 प्रतिशत से अधिक किसानों को लाभ मिला है लेकिन योजनाओं से कम लाभ रखने वाले किसानों की तुलना कम है परन्तु चयनित विकास योजना में से कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसके बारे में सर्वेक्षित उत्तरदाता को जानकारी न हो सभी किसानों तक पहुँचने के लिए शासन सशक्त कदम उठा रहा है।

आरेख क्रमांक–1
कृषि और ग्रामीण संबंधित सरकारी योजनाओं की लाभ स्थिति

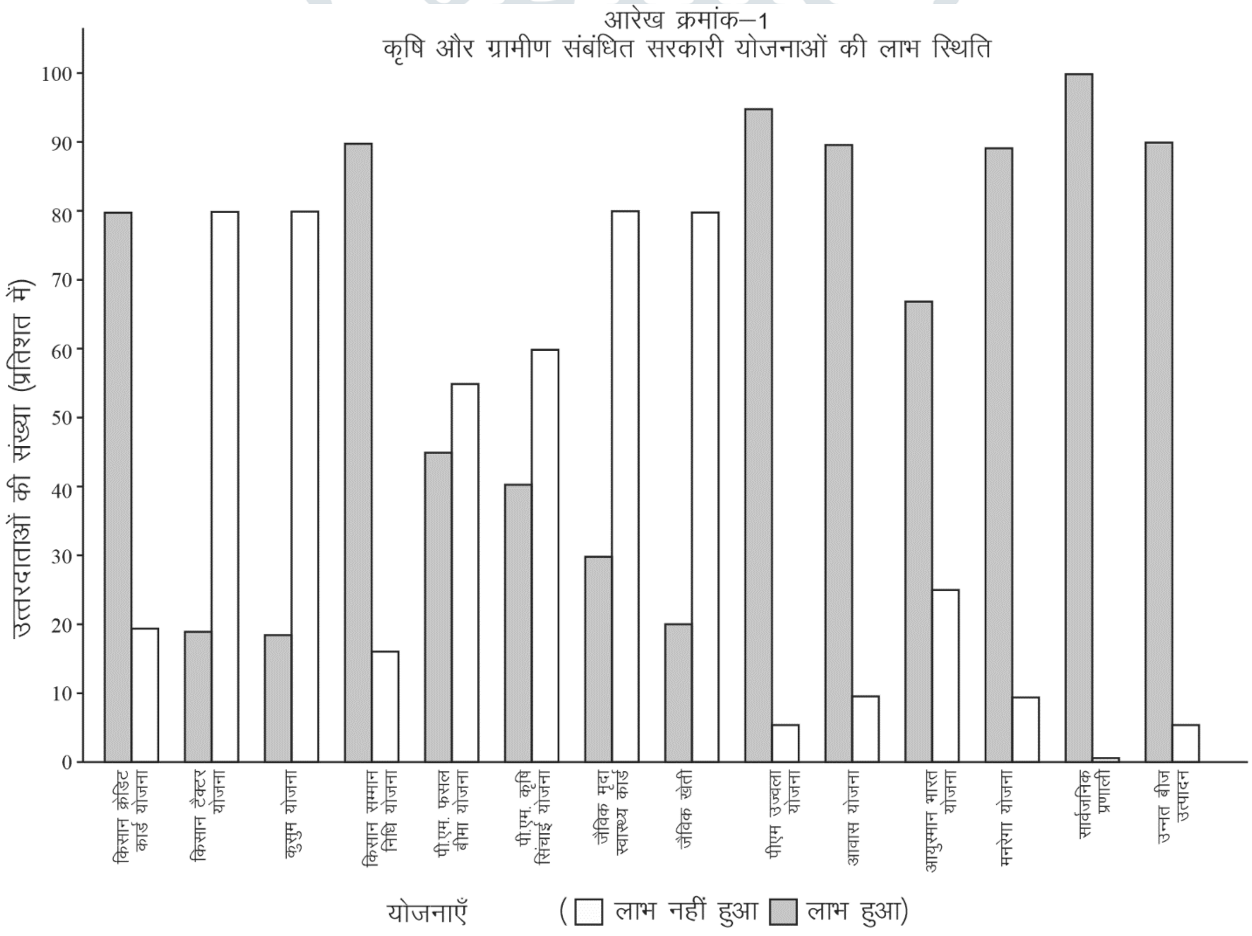

तालिका क्रमांक–2

किसान और ग्रामीणों के आय में वृद्धि से उनके जीवन में परिवर्तन की स्थिति

क्र.सं.	ग्रामीण किसान के जीवन स्तर में परिवर्तन	परिवर्तन हुआ	परिवर्तन नहीं हुआ	योग
1.	मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति	70	30	100
2.	राशन की व्यवस्था	100	00	100
3.	शिक्षा का स्तर	75	25	100
4.	पक्का घर निर्माण	85	15	100
5.	पेय जल की व्यवस्था	85	15	100
6.	आधुनिक कृषि यंत्र	60	40	100
7.	24 घण्टों बिजली की व्यवस्था	70	30	100
8.	रोजगार में वृद्धि	70	30	100
9.	तकनीकी सुविधायें	60	40	100
10.	पलायन में कमी	80	20	100

आरेख क्रमांक–2

किसानों और ग्रामीणों के आय में वृद्धि से उनके जीवन स्तर में परिवर्तन की स्थिति

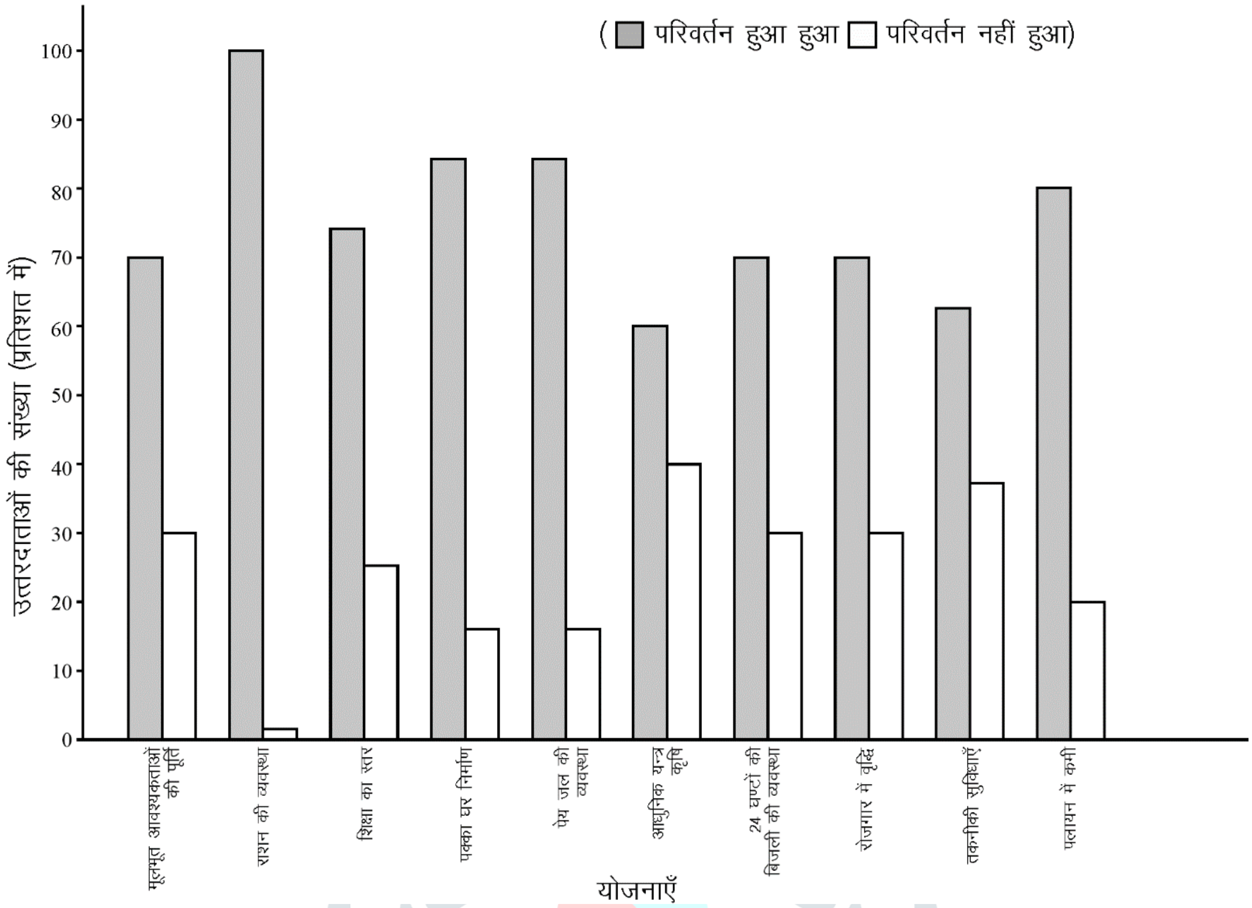

उपर्युक्त तालिका व आरेख क्रमांक–2 से स्पष्ट होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के क्षेत्र में 70 प्रतिशत सकारात्मक प्रगति हुई है जैसा कि राशन की व्यवस्था में 100 प्रतिशत और पक्के घरों का निर्माण में 85 प्रतिशत साथ ही शिक्षा के स्तर में 75 प्रतिशत और पेयजल की व्यवस्था में 85 प्रतिशत सुधार हुआ है। पलायन में कमी 80 प्रतिशत और किसानों को रोजगार के मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है।

निष्कर्ष–

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जगत विकास खण्ड में मानव, मशीन, पदार्थ, मानवीय पूँजी, पर्यावरण नवीन प्रौद्योगिकी और कृषि में नवाचार के बीच उच्चस्तर का सन्तुलन प्राप्त किया गया है और सरकार द्वारा मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ जनपद बदायूँ के जगत ब्लॉक के किसानों को मिल रहा है। जिसके कारण ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो रही है। किसान स्वयं के विकास के साथ–साथ अपने परिवार का भी विकास कर रहा है। गाँवों को भारतीय समाज की नींव और लघु दर्पण के रूप में देखा जाता है, जो आज कृषि के माध्यम से अपने जीवन को समद्ध बना रहे हैं। इससे ग्रामीणों का नहीं बल्कि पूरे देश का विकास हो रहा है, क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और उनके साथ–साथ कृषि की अधिकतम उपयोगिता, देश के समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं।

सुझाव के रूप में, जो किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं सरकार को चाहिए जो भी योजना चलाए गाँव के प्रधान और अधिकारियों के बिना भेदभाव करे किसानों को जानकारी प्रदान करें। विभाग में नागरिक घोषणा–पत्र को

पारदर्शी रूप से लागू किया जाये और सभी योजनाओं से सम्बन्धिक अधिकारियों की जबाव देही सुनिश्चित की जाये, तथा इनका मूल्यांकन सतत होना चाहिए।

सन्दर्भ :–

1. [1]ज्योति निषाद[2] डॉ. (श्रीमती) संतोष जैन

   ''सरकार की विभिन्न योजनाओं से कृषि में नवाचार एवं ग्रामीण विकास'' (दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड के विशेष सन्दर्भ में)

   An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal 2023 IJCRT, Volume II, Issue 3 March 2023, ISSN : 2320-2882

2. डॉ. कुशल जैन कोठारी, श्रीमती दीपिका त्रिवेदी 'ग्रामीण विकास में शिक्षा की प्रभावशीलता' राधाकमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा Regd. No. UPHIN/1999/00955 ISSN 0974-0074 वर्ष 25 अंक 1, जनवरी–जून 2023 UGC-CARE List-Social Sciences.

3. डॉ. शकुन्तला मीना 'ग्रामीण विकास की अवधारणा, बाधाएँ एवं शिक्षा की भूमिका' International Journal of Education, Modern Management, Applied Science (IJEMMASS), April-June 2021, ISSN : 2581-9925.

4. सतत् और समावेशी ग्रामीण विकास, कुरूक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित), नई दिल्ली, जून 2021 वर्ष 67, मासिक अंक 8, पृ.–25

5. योजना–अगस्त 2006

6. योजना–अक्टूबर 2023

7. योजना–नवम्बर 2023

8. भारत–2017

9. भारत–2023

10. न्यू इण्डिया समाचार (16–30 अप्रैल, 2022)

11. प्रो. वी. एल. ओसा, डॉ. अनुपम अग्रवाल (2014)

12. डॉ. चतुर्भुज मामोरिया एवं एड. सी. जैन (1991)

13. सांख्यिकीय पत्रिका, बदायूँ

14. Sarkari Yojanayen

15. https ://tractargyan.com

16. https : //www.india.gov.in

17. https ://narega.net>PMSchemes

18. https : //www.nibsm.org.in

19. https ://www. इंडिया, सरकार भारत

20. https : //budaun.nic.in

21. https : // updes.up.nic.in